NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

दैनिक समाचार विश्लेषण

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 10 Oct, 2025

Edition : InternationalTable of Contents

Page 01 Syllabus : GS 2 &3 : I.R. &Science and tech/ Prelims	भारत 35 करोड़ पाउंड में ब्रिटेन से मिसाइलें खरीदेगा
Page 01 Syllabus : Prelims	लास्ज़लो क्राज़्नाहोरकाई को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला
Page 07 Syllabus : GS 3 : Science and tech / Prelims	हमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बारे में बात करने का तरीका क्यों बदलना होगा
Page 10 Syllabus : GS 2 : Indian Polity/ Prelims	चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न रूप क्या हैं?
Page 14 Syllabus : GS 2 : International Relations / Prelims	जेन जेड के विरोध प्रदर्शन के एक महीने बाद, नेपाल को लोकतांत्रिक सुधार के लिए एक कठिन रास्ते का सामना करना पड़ रहा है
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus : GS 2 : Social Justice	भारतकामानसिकस्वास्थ्यसंकट, रोनाऔरजख्म

Page 01 :GS 2 & 3 : I.R. &Science and tech/ Prelims

भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी **को बढ़ावा देने के लिए**, भारतनेभारतीयसेनाकेलिए**लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइलों (LMM)** की खरीद के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ **£ 350 मिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता** ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर **की भारत यात्रा के साथ मेल खाता है**, जो **द्विपक्षीय रक्षा, आर्थिक, और हाल** ही में संपन्न **भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)** के तहत शैक्षिक सहयोग।

इसके अतिरिक्त, दोनों देशों ने **नौसेना के जहाजों के लिए बिजली से चलने वाले इंजन** विकसित करने के लिए **£ 250 मिलियन के सहयोग पर हस्ताक्षर किए, जो** हरित रक्षा प्रौद्योगिकियों **और आत्मनिर्भरता** की ओर एक बदलाव पर प्रकाश डालता है।

India will buy U.K. missiles for £350 mn

The U.K. govt. says as many as 64 Indian firms have committed to invest £1.3 billion in Britain

Modi and Keir Starmer agree on a £250-million deal on electric-powered engines for Naval ships

The Universities of Lancaster and Surrey receive approval to open campuses in India

The Hindu Bureau
NEW DELHI

India has signed a £350-million defence deal with the U.K. to buy missiles for the Indian army, the British government said on Thursday.

Prime Minister Narendra Modi and his U.K. counterpart, Keir Starmer, also agreed to take forward their collaboration on electric-powered engines for Naval ships, worth an initial £250 million.

In a separate release, the U.K. government said 64 Indian companies had so far committed to invest £1.3 billion (or ₹15,430 crore) in the U.K., a sign of the growing business confidence boosted by the India-U.K. trade deal.

U.K. varsities in India

The Indian government has not shared similar data on investment commitments by U.K. companies in India.

However, the U.K. government also said that the University of Lancaster and the University of Surrey had been given approval to open campuses in India to help meet booming demand from Indian students.

The missile deal paves the way for a "broader complex weapons partnership" between the U.K. and India, which is currently under negotiation between the two governments, the U.K. government said in its statement.

"The contract is set to deliver U.K.-manufactured Lightweight Multirole Missiles (LMM) built in Belfast to the Indian Army, delivering on the Government's Plan for Change in another significant boost for the U.K. defence industry," it said.

"A new milestone has also been reached in the U.K. and India's cooperation on electric-powered engines for naval ships as both countries signed the Implementing Arrangement to advance collaboration to the next stage, worth an initial £250 million," it added.

Building cooperation: Prime Minister Narendra Modi with British Prime Minister Keir Starmer at the Raj Bhavan in Mumbai on Thursday. PTI

"Nearly 7,000 brand new jobs will be created in the United Kingdom thanks to a raft of major new deals secured by the Prime Minister during his visit to India this week," the U.K. government said. "As a result, Indian investment will flow into a range of U.K. sectors including engineering, technology and the creative industries, driving growth and creating jobs across every region of the country - from Basingstoke to Birmingham," it added.

Among the major investment announcements are TVS Motor's plan to invest £250 million in Solihull to expand its Norton Motorcycles operations and develop next-generation electric vehicles.

"Engineering company Cyient is investing £100 million to boost innovation in semiconductors, geospatial tech, mobility, clean energy, and digital domains – creating 300 U.K. jobs and strengthening its long-standing presence in the country," the release said.

Muthoot Finance UK Limited, a part of the Muthoot Group, plans to invest £100 million to expand its branch network to 20 locations in the U.K. Hero Motors plans to invest £100 million in the U.K. over the next five years in its e-mobility, e-bicycles and aerospace divisions.

The Hindu has reached out to the Ministry of Commerce and Industry for details on investment announcements by U.K. companies in India.

On the first day of Mr. Starmer's visit to India, Rolls-Royce CEO Tufan Erginbilgic said that his company has "deep ambitions to develop India as a home for Rolls-Royce".

'India-U.K. ties an important pillar of global stability'

MUMBAI/NEW DELHI

Prime Minister Narendra Modi, who welcomed his U.K. counterpart Keir Starmer on Thursday, said the India-U.K. partnership was an "important pillar of global stability" in the current turbulent global scenario. Both the Prime Ministers also gave a joint call for a "two-state solution" to end the Israel-Palestine conflict. » PAGE 4

यात्रा और समझौतों की मुख्य विशेषताएं

1. रक्षा सहयोग

- **मिसाइल डील:**
  - मूल्य £ **350 मिलियन (लगभग ₹ 3,700 करोड़)।**
  - भारत बेलफास्ट में निर्मित ब्रिटेन से लाइटवेट **मल्टीरोल मिसाइल (एलएएमएम)** खरीदेगा।

- संयुक्त रक्षा अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन को गहरा करने के लिए बातचीत के तहत **एक बड़ी "जटिल हथियार साझेदारी"** का हिस्सा।

- **नौसेना इलेक्ट्रिक इंजन:**
  - **एक कार्यान्वयन व्यवस्था के** तहत बिजली से चलने वाले जहाज इंजनों के लिए **£ 250 मिलियन का समझौता**।
  - हरित नौसेना प्रौद्योगिकी और सतत समुद्री रक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है।

2. व्यापार और निवेश

- **यूके में भारतीय निवेश:**
  - 64 भारतीय कंपनियां **£1.3 बिलियन (~₹15,430 करोड़) का निवेश करेंगी**।
  - यूके में इंजीनियरिंग, स्वच्छ ऊर्जा, तकनीक और रचनात्मक क्षेत्रों में **7,000 नौकरियां** पैदा करने की उम्मीद है।

प्रमुख घोषणाएँ:

  - **टीवीएस मोटर** - सोलीहुल में ईवी और नॉर्टन मोटरसाइकिलों के लिए £250 मिलियन।
  - **साइएंट** - अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा और गतिशीलता में नवाचार के लिए £ 100 मिलियन।
  - **मुथूट फाइनेंस यूके लिमिटेड** - शाखाओं का विस्तार करने के लिए £100 मिलियन।
  - **हीरो मोटर्स** - ई-मोबिलिटी और एयरोस्पेस विस्तार के लिए £ 100 मिलियन।
- **भारत में यूके विश्वविद्यालय:**
  - **लैंकेस्टर विश्वविद्यालय** और **सरे विश्वविद्यालय** ने भारत में परिसर खोलने को मंजूरी दी – भारत की **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत** विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कदम।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	**वर्तमान प्रासंगिकता**
भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2021)	रक्षा, व्यापार, जलवायु, शिक्षा और नवाचार में सहयोगकेलिएरूपरेखा।
रक्षाऔद्योगिकगलियारे	एलएमएम और नौसेना इंजनों का संयुक्त उत्पादन आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की स्वदेशी क्षमताओं को मजबूतकरसकता**है**।
रक्षाखरीदनीति (डीपीपी) 2020	भारतीय फर्मों को विदेशी सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देता है।
हरितरक्षाप्रौद्योगिकियां	विद्युत प्रणोदन **स्थायी समुद्री लक्ष्यों** और **नीली अर्थव्यवस्था की दृष्टि के** अनुरूप है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020	शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति दी।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

1. रक्षा संबंधों को मजबूत करना

- भारत-ब्रिटेन सुरक्षा संबंधों को बातचीत से परे संयुक्त **विकास और सह-उत्पादन तक विस्तारित करना**।
- रणनीतिक पारस्परिकता **को बढ़ाता** है और भारत के **रक्षा आधुनिकीकरण का समर्थन करता है**।
- वैश्विक भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण के बीच **आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण** में योगदान देता है।

2. आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा

- यह दोतरफा निवेश प्रवाह **को दर्शाता है**, न कि केवल व्यापार।
- आपसी विकास और रोजगार सृजन **के लिए एक मंच के रूप में** भारत-ब्रिटेन एफटीए **को मजबूत करता है**।
- सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, ईवी और फिनटेक **में सहयोग को प्रोत्साहित करता है** - भारत के 2047 विजन के प्रमुख क्षेत्र

3. शिक्षा और सॉफ्ट पावर

- यूके विश्वविद्यालय परिसरों के खुलने से **ज्ञान के आदान-प्रदान और लोगों से लोगों के बीच संबंध** गहरे होंगे।
- वैश्विक शिक्षा केंद्र **बनने की भारत की आकांक्षा का समर्थन करता है**।

रणनीतिक निहितार्थ

- शुद्ध आयात के बजाय सह-विकास के माध्यम से **भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को** मजबूत करता है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **भारत की समुद्री क्षमताओं** को मजबूत करता है।
- यह यूके की इंडो-पैसिफिक टिल्ट **पॉलिसी और भारत की** एक्ट ईस्ट एंडइंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव **के अनुरूप है**।

आगे की चुनौतियाँ

- "मेक इन इंडिया" के तहत **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्थानीय विनिर्माण** सुनिश्चित करना।
- अन्य रक्षा आपूर्तिकर्ताओं (अमेरिका, फ्रांस, रूस) के साथ रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करना।
- भारत में ब्रिटेन के निवेश के आंकड़ों के बाद से **व्यापार संतुलन** की निगरानी स्पष्ट नहीं है।
- वीजा और गतिशीलता के मुद्दों **का प्रबंधन**, जो एफटीए ढांचे से बाहर हैं।

निष्कर्ष

£ 350 मिलियन मिसाइल सौदा और £ 250 मिलियन नौसेना इंजन सहयोग **भारत-ब्रिटेन रणनीतिक संबंधों में एक नया अध्याय** है, जो व्यापार और शिक्षा से लेकर उच्च तकनीक रक्षा और स्थिरता तक सहयोग का विस्तार करता है। भारत-ब्रिटेन एफटीए के साथ, ये विकास **विश्वास, प्रौद्योगिकी और व्यापार की एक आधुनिक साझेदारी** का प्रतीक हैं, जो दोनों देशों के सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत औरविकसित भारत @2047 **के साझा दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण** है।

दैनिक समाचार विश्लेषण

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: नौसैनिक प्रौद्योगिकी में भारत-ब्रिटेन सहयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दोनों देश नौसेना के जहाजों के लिए बिजली से चलने वाले इंजनों पर सहयोग करने पर सहमत हुए।

2. समझौते का मूल्य प्रारंभिक £250 मिलियन है।

3. यह पहल "वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड" वैश्विक ऊर्जा ढांचे का हिस्सा है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर : a)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारतऔरब्रिटेनके बीच हाल ही में हुए रक्षा और व्यापार समझौते एक परिपक्व रणनीतिक साझेदारी को दर्शाते हैं। भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक कूटनीति के संदर्भ में इन घटनाक्रमों के महत्व पर चर्चा कीजिए। **(250 शब्द)**

दैनिक समाचार विश्लेषण

Page 01 : Prelims

साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार हंगेरियन उपन्यासकार **लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई** को दिया गया, जो अपने **दूरदर्शी, दार्शनिक और शैलीगत रूप से जटिल लेखन के लिए प्रसिद्ध थे**। स्वीडिश अकादमी ने उन्हें उनके "सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए सम्मानित किया, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच, कला की शक्ति की पुष्टि करता है।

उनकी मान्यता कला के माध्यम से अराजकता, निराशा और आशा का पता लगाने की साहित्य की स्थायी क्षमता को मजबूत करती है, विशेष रूप से कम्युनिस्ट और मध्य यूरोपीय अनुभव से।

László Krasznahorkai wins Nobel Prize in literature

Associated Press
STOCKHOLM

Hungarian writer László Krasznahorkai, whose philosophical, bleakly funny novels often unfold in single sentences, won the Nobel Prize in literature on Thursday for his "compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art".

The Nobel judges praised his "artistic gaze which is entirely free of illusion, and which sees through the fragility of the social order combined with his unwavering belief in the power of art," Steve Sem-Sandberg of the Nobel committee said at the announcement.

"László Krasznahorkai is a great epic writer in the Central European tradition that extends through [Franz] Kafka to Thomas Bernhard, and is characterised by absurdism and grotesque excess," the Nobel judges said.

Several works, including his debut, *Satantango*, and *The Melancholy of Resistance* were turned into films by Hungarian director Béla Tarr.

Mr. Krasznahorkai, 71, could not immediately be reached for his reaction. He did not speak at the announcement.

He was born in the southeastern Hungarian city of Gyula, near the border with Romania.

László Krasznahorkai, who won the Nobel Prize in Literature; and some of his books on display in Stockholm. FILE PHOTOS

Political critic

Throughout the 1970s, he studied law at universities in Szeged and Budapest before shifting his focus to literature.

Mr. Krasznahorkai has been a vocal critic of autocratic Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, especially his government's lack of support for Ukraine after the Russian invasion.

But in a post on Facebook, Mr. Orbán was quick to congratulate the writer, saying: "The pride of Hungary, the first Nobel Prize winner from Gyula, László Krasznahorkai. Congratulations!"

In an interview with Swedish newspaper *Svenska Dagbladet* earlier this year, Mr. Krasznahorkai expressed criticism both of Mr. Orbán's political system and the nationalism present in Hungarian society. "There is no hope left in Hungary today and it is not only because of the Orbán regime," he told the paper. "The problem is not only political, but also social." He also reflected on the fact that he has long been a contender for the Nobel Prize in literature, saying: "I don't want to lie. It would be very interesting to get that prize. But I would be very surprised if I got it."

The Booker judges praised his "extraordinary sentences, sentences of incredible length that go to incredible lengths, their tone switching from solemn to madcap to quizzical to desolate as they go their wayward way."

He also won the National Book Award for Translated Literature in the U.S. in 2019 for *Baron Wenckheim's Homecoming*.

पुरस्कार विजेता के बारे में

- **नाम:** László Krasznahorkai
- **राष्ट्रीयता:** हंगेरियन
- **जन्म:** 1954, ग्युला (रोमानिया सीमा के पास)

- **शिक्षा:** साहित्य की ओर मुड़ने से पहले सेगेड और बुडापेस्ट विश्वविद्यालयों में कानून का अध्ययन किया।
- **उल्लेखनीय कार्य:**

  · सातांतांगो (1985)

  · प्रतिरोध की उदासी (1989)

  · बैरन वेन्कहाइम की घर वापसी (2016)

  · युद्ध और युद्ध (1999)

इनमें से कई उपन्यासों को प्रसिद्ध हंगेरियन फिल्म निर्माता बेला टार द्वारा फिल्मों में रूपांतरित किया गया था।

लेखन शैली और विषय-वस्तु

- **विशिष्ट शैली:**
  - असाधारण रूप से लंबे वाक्यों के लिए जाना जाता है, कभी-कभी पूरे अध्यायों में फैला होता है।
  - उनका गद्य **दर्शन, बेतुकापन और गहरे हास्य का मिश्रण है**, जो मानवीय निराशा और सहनशक्ति की खोज करता है।
- **केंद्रीय विषय-वस्तु:**
  - **सामाजिक व्यवस्था का पतन** और अधिनायकवाद का उदय।
  - अराजकता **के बीच** अर्थ की खोज।
  - **सर्वनाशकारी कल्पना** और आधुनिकता की आलोचना।
  - कला की परिवर्तनकारी शक्ति **में गहरा विश्वास**।

नोबेल समिति ने उनकी शैली की तुलना **फ्रांज काफ्का** और **थॉमस बर्नहार्ड** से की, जिससे उन्हें **मध्य यूरोपीय अस्तित्ववादी साहित्यिक परंपरा के भीतर रखा गया**।

राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ

- क्रास्ज़नाहोरकाई**हंगरीकेप्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन और** हंगरी में **राष्ट्रवादी सत्तावादी राजनीति** के उदय के मुखर आलोचक रहे हैं।
- वह आधुनिक पूर्वी यूरोप में एक असहमतिपूर्ण कलात्मक आवाज **का प्रतिनिधित्व करता** है - प्रतिरोध के रूप में साहित्य का उपयोग करता है।
- उनकी आलोचना के बावजूद, हंगरी सरकार ने सार्वजनिक रूप से उन्हें बधाई दी, उनके **नोबेल से मिले** राष्ट्रीय गौरव को मान्यता दी।

उनके काम व्यापक यूरोपीय उत्तर-अधिनायकवादी चिंताओं **को भी प्रतिध्वनित करते हैं**, जो लोकतंत्र और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की समकालीन चर्चाओं में प्रासंगिक हैं।

दैनिक समाचार विश्लेषण

यूपीएससी के लिए स्थिर और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक अवधारणा	**कनेक्शन**
साहित्य में नोबेल पुरस्कार	अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के तहत 1901 में स्थापित; **स्वीडिश अकादमी** द्वारा उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए "एक आदर्श दिशा में" सम्मानित किया गया।
मध्य यूरोपीय साहित्यिक परंपरा	काफ्का, कुंदेरा, बर्नहार्ड शामिल हैं - अक्सर बेतुकेपन, अलगाव और राज्य उत्पीड़न के विषयों की पड़ताल करता है।
साहित्य और समाज	यूपीएससी जीएस । पाठ्यक्रम सामाजिक परिवर्तन के प्रतिबिंब के रूप में कला और साहित्य की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	जीएस ॥ विषयों से जुड़ता है - लोकतंत्र, मानवाधिकार और सांस्कृतिक स्वतंत्रता।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

1. पुरस्कार का महत्व

- साहित्य को अधिनायकवाद और दुष्प्रचार के युग में **प्रतिरोध के रूप में** पहचानता है।
- शक्ति संरचनाओं और नैतिक क्षय पर सवाल उठाने के लिए **कथा की शक्ति को** मजबूत करता है।
- राष्ट्रवाद और उदार मूल्यों के बीच **यूरोप के चल रहे संघर्ष का प्रतीक है**।

2. भारत का सीखने का संदर्भ

- इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि लेखक **नैतिक टिप्पणीकारों और सामाजिक आलोचकों के रूप में कैसे कार्य कर सकते हैं**।
- क्षेत्रीय और स्थानीय साहित्य **के लिए समर्थन को प्रोत्साहित करता** है जो समान दार्शनिक और सामाजिक विषयों की खोज करता है।

निष्कर्ष

साहित्य में लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई का नोबेल पुरस्कार एक खंडित दुनिया में **गंभीर, आत्मनिरीक्षण लेखन की स्थायी प्रासंगिकता** को रेखांकित करता है। उनकी रचनाएँ - कला की मोचन शक्ति के साथ निराशा का मिश्रण - हमें याद दिलाती हैं कि राजनीतिक **और अस्तित्वगत संकटों के बीच** आशा को प्रतिबिंबित करने, विरोध करने और पुन: पुष्टि करने के लिए साहित्य मानवता के सबसे मजबूत उपकरणों में से एक है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/सेकथनसहीहै/हैं?

1. वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन हैं।

2. उनके उपन्यास लंबे, जटिल वाक्यों और दार्शनिक विषयों के लिए जाने जाते हैं।

3. उनके कुछ कार्यों को हंगेरियन निर्देशक बेला टार द्वारा फिल्मों में रूपांतरित किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए:

A. केवल 1

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

Page 07 : GS 3 : Science and tech / Prelims

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) - जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी उन्हें मारने के लिए डिज़ाइन की गई दवाओं का विरोध करने के लिए विकसित होते हैं - 21 वीं सदी की सबसे गंभीर वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। हालांकि, जैसा कि **डॉ. अब्दुल गफूर** का तर्क है, एएमआर आज न केवल एक **चिकित्सा या वैज्ञानिक संकट है** , बल्कि एक **संचार संकट भी है**। जिस तरह से हम एएमआर के बारे में बात करते हैं - भय, आंकड़े और भविष्य की आपदाओं के साथ - ने लोगों को स्थानांतरित करने की अपनी शक्ति खो दी है। ध्यान बनाए रखने और कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए, हमें **भय-आधारित से मानव-केंद्रित संचार में बदलाव की आवश्यकता है**।

दैनिक समाचार विश्लेषण

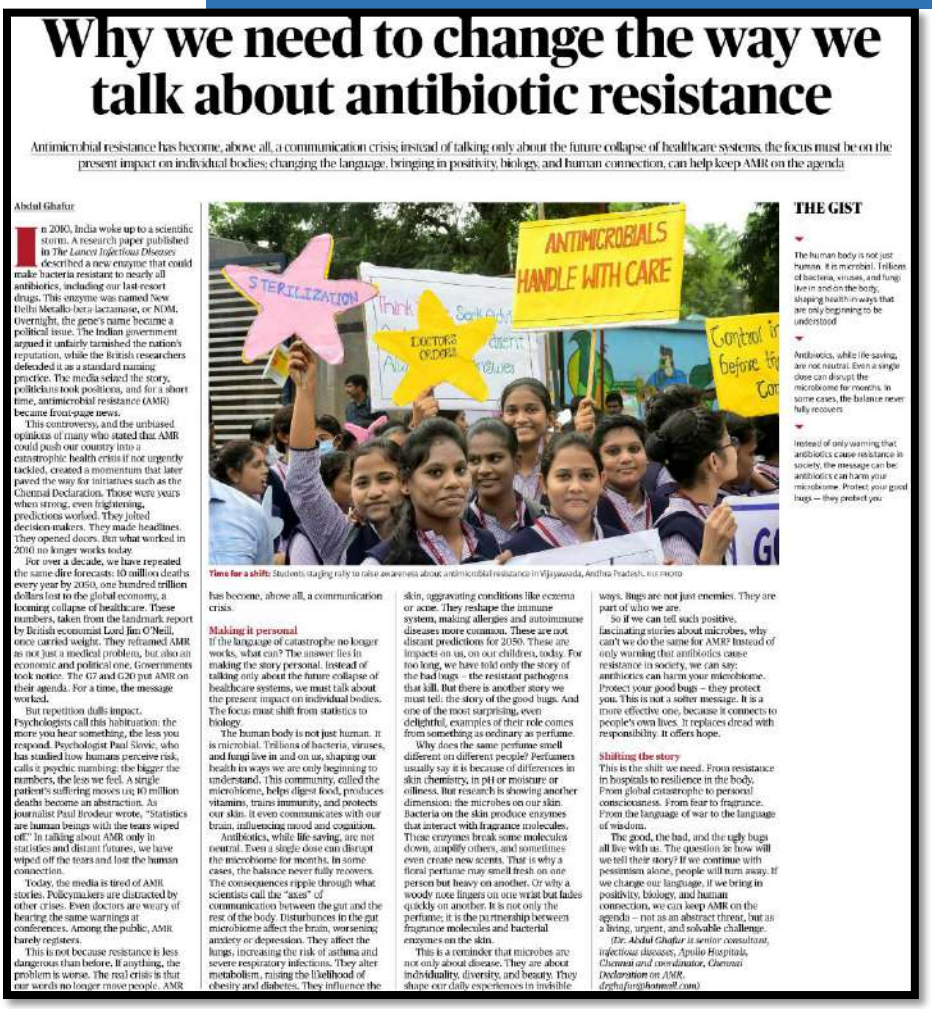

Why we need to change the way we talk about antibiotic resistance

Antimicrobial resistance has become, above all, a communication crisis; instead of talking only about the future collapse of healthcare systems, the focus must be on the present impact on individual bodies; changing the language, bringing in positivity, biology, and human connection, can help keep AMR on the agenda

Abdul Ghafur

In 2010, India woke up to a scientific storm. A research paper published in *The Lancet Infectious Diseases* described a new enzyme that could make bacteria resistant to nearly all antibiotics, including our last-resort drugs. This enzyme was named New Delhi Metallo-beta-lactamase, or NDM. Overnight, the gene's name became a political issue. The Indian government argued it unfairly tarnished the nation's reputation, while the British researchers defended it as a standard naming practice. The media seized the story, politicians took positions, and for a short time, antimicrobial resistance (AMR) became front-page news.

This controversy, and the unbiased opinions of many who stated that AMR could push our country into a catastrophic health crisis if not urgently tackled, created a momentum that later paved the way for initiatives such as the Chennai Declaration. Those were years when strong, even frightening, predictions worked. They jolted decision-makers. They made headlines. They opened doors. But what worked in 2010 no longer works today.

For over a decade, we have repeated the same dire forecasts: 10 million deaths every year by 2050, one hundred trillion dollars lost to the global economy, a looming collapse of healthcare. These numbers, taken from the landmark report by British economist Lord Jim O'Neill, once carried weight. They reframed AMR as not just a medical problem, but also an economic and political one. Governments took notice. The G7 and G20 put AMR on their agenda. For a time, the message worked.

But repetition dulls impact. Psychologists call this habituation: the more you hear something, the less you respond. Psychologist Paul Slovic, who has studied how humans perceive risk, calls it psychic numbing: the bigger the numbers, the less we feel. A single patient's suffering moves us; 10 million deaths become an abstraction. As journalist Paul Brodeur wrote, "Statistics are human beings with the tears wiped off." In talking about AMR only in statistics and distant futures, we have wiped off the tears and lost the human connection.

Today, the media is tired of AMR stories. Policymakers are distracted by other crises. Even doctors are weary of hearing the same warnings at conferences. Among the public, AMR barely registers.

This is not because resistance is less dangerous than before. If anything, the problem is worse. The real crisis is that our words no longer move people. AMR has become, above all, a communication crisis.

Making it personal

If the language of catastrophe no longer works, what can? The answer lies in making the story personal. Instead of talking only about the future collapse of healthcare systems, we must talk about the present impact on individual bodies. The focus must shift from statistics to biology.

The human body is not just human. It is microbial. Trillions of bacteria, viruses, and fungi live in and on us, shaping our health in ways we are only beginning to understand. This community, called the microbiome, helps digest food, produces vitamins, trains immunity, and protects our skin. It even communicates with our brain, influencing mood and cognition.

Antibiotics, while life-saving, are not neutral. Even a single dose can disrupt the microbiome for months. In some cases, the balance never fully recovers. The consequences ripple through what scientists call the "axes" of communication between the gut and the rest of the body. Disturbances in the gut microbiome affect the brain, worsening anxiety or depression. They affect the lungs, increasing the risk of asthma and severe respiratory infections. They alter metabolism, raising the likelihood of obesity and diabetes. They influence the skin, aggravating conditions like eczema or acne. They reshape the immune system, making allergies and autoimmune diseases more common. These are not distant predictions for 2050. These are impacts on us, on our children, today. For too long, we have told only the story of the bad bugs – the resistant pathogens that kill. But there is another story we must tell: the story of the good bugs. And one of the most surprising, even delightful, examples of their role comes from something as ordinary as perfume.

Why does the same perfume smell different on different people? Perfumers usually say it is because of differences in skin chemistry, in pH or moisture or oiliness. But research is showing another dimension: the microbes on our skin. Bacteria on the skin produce enzymes that interact with fragrance molecules. Those enzymes break some molecules down, amplify others, and sometimes even create new scents. That is why a floral perfume may smell fresh on one person but heavy on another. Or why a woody note lingers on one wrist but fades quickly on another. It is not only the perfume; it is the partnership between fragrance molecules and bacterial enzymes on the skin.

This is a reminder that microbes are not only about disease. They are about individuality, diversity, and beauty. They shape our daily experiences in invisible ways. Bugs are not just enemies. They are part of who we are.

So if we can tell such positive, fascinating stories about microbes, why can't we do the same for AMR? Instead of only warning that antibiotics cause resistance in society, we can say: antibiotics can harm your microbiome. Protect your good bugs – they protect you. This is not a softer message. It is a more effective one, because it connects to people's own lives. It replaces dread with responsibility. It offers hope.

Shifting the story

This is the shift we need. From resistance in hospitals to resilience in the body. From global catastrophe to personal consciousness. From fear to fragrance. From the language of war to the language of wisdom.

The good, the bad, and the ugly bugs all live with us. The question is: how will we tell their story? If we continue with pessimism alone, people will turn away. If we change our language, if we bring in positivity, biology, and human connection, we can keep AMR on the agenda – not as an abstract threat, but as a living, urgent, and solvable challenge.

Dr. Abdul Ghafur is senior consultant, infectious diseases, Apollo Hospitals, Chennai and coordinator, Chennai Declaration on AMR. drghafur@hotmail.com)

THE GIST

- The human body is not just human. It is microbial. Trillions of bacteria, viruses, and fungi live in and on the body, shaping health in ways that we are only beginning to be understood
- Antibiotics, while life-saving, are not neutral. Even a single dose can disrupt the microbiome for months. In some cases, the balance never fully recovers
- Instead of only warning that antibiotics cause resistance in society, the message can be: antibiotics can harm your microbiome. Protect your good bugs — they protect you

Time for a shift: Students staging rally to raise awareness about antimicrobial resistance in Vijayawada, Andhra Pradesh. FILE PHOTO

वर्तमान संदर्भ

- 2010 में एनडीएम (नई दिल्ली मेटालो-बीटा-लैक्टामेज़) **के बारे में बहस** ने एएमआर के बारे में भारत की जागरूकता को जन्म दिया और **चेन्नई घोषणा (2012) जैसी पहल को जन्म दिया**।
- प्रारंभ में, गंभीर पूर्वानुमानों (जैसे "2050 तक 10 मिलियन मौतें") ने नीति निर्माताओं को ध्यान देने में मदद की।
- लेकिन समय के साथ, इस तरह की बार-बार चेतावनियों ने **मानसिक सुन्नता का** कारण बना - समाज संदेश के प्रति असंवेदनशील हो गया।
- लेखक का सुझाव है कि एएमआर संचार को अब **वर्तमान, व्यक्तिगत और जैविक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए** - जैसे कि एंटीबायोटिक्स मानव माइक्रोबायोम को कैसे बाधित करते हैं - केवल भविष्य के वैश्विक पतन के बजाय।

स्थैतिक संबंध

1. रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) क्या है?

एएमआर तब होता है जब सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया, कवक, वायरस, परजीवी) समय के साथ बदलते हैं और दवाओं का जवाब नहीं देते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है।

कारण:

- मनुष्यों और जानवरों में एंटीबायोटिक दवाओं का अति प्रयोग और दुरुपयोग
- खराब संक्रमण नियंत्रण और स्वच्छता
- अपर्याप्त अपशिष्ट जल प्रबंधन
- एंटीबायोटिक दवाओं की अनियमित बिक्री

उदाहरण:

- मेथिसिलिन प्रतिरोधी स्टैफिलोकोकस ऑरियस (एमआरएसए)
- एनडीएम-1 (नई दिल्ली मेटालो-बीटा-लैक्टामेज़) एंजाइम

2. प्रमुख वैश्विक और भारतीय पहल

स्तर	पहल	विवरण
वैश्विक	**एएमआर पर डब्ल्यूएचओ की वैश्विक कार्य योजना (2015)**	इसका उद्देश्य एक-स्वास्थ्य दृष्टिकोण और जिम्मेदार रोगाणुरोधी उपयोग है।
	वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली (GLASS)	वैश्विक स्तर पर एएमआर रुझानों की निगरानी करता है।
भारत	**एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2017-2021)**	मानव, पशु, खाद्य और पर्यावरण क्षेत्रों में रणनीति।
	चेन्नई घोषणा (2012)	भारतीय डॉक्टरों और नीति निर्माताओं द्वारा बहु-हितधारक रोडमैप।
	आईसीएमआर-एएमआर निगरानी नेटवर्क	पूरे भारत में प्रतिरोध पैटर्न को ट्रैक करता है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

1. संचार संकट के रूप में एएमआर

- प्रारंभिक दृष्टिकोण भय-आधारित संदेश पर निर्भर था: "2050 तक 10 मिलियन मौतें," "आधुनिक चिकित्सा का पतन।
- इस तरह की पुनरावृत्ति ने नीति निर्माताओं, डॉक्टरों और जनता के बीच असंवेदनशीलता पैदा कर दी।
- इसलिए, एएमआर संदेश अब **भावनात्मक रूप से संबंधित होना चाहिए**, न कि केवल सांख्यिकीय रूप से चिंताजनक।

दैनिक समाचार विश्लेषण

2. संचार रणनीति में बदलाव

से	**तक**
भय और तबाही	जीव विज्ञान और व्यक्तिगत प्रभाव
प्रतिरोध कथा	लचीलापन कथा
वैश्विक संकट	व्यक्तिगत चेतना
स्टैटिस्टिक्स	मानवीय कहानियाँ
युद्ध की भाषा ("सुपरबग")	बुद्धि भाषा ("अच्छे और बुरे कीड़े सह-अस्तित्व"

3. माइक्रोबायोम की भूमिका

- मानव शरीर खरबों रोगाणुओं की मेजबानी करता है - **माइक्रोबायोम -** पाचन, प्रतिरक्षा, मनोदशा और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
- एंटीबायोटिक्स इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करते हैं, जिससे एलर्जी, मोटापा, चिंता या ऑटोइम्यून बीमारियों जैसे दुष्प्रभाव होते हैं।
- इसलिए, **माइक्रोबायोम की रक्षा करना = स्वयं की रक्षा करना** - एक संदेश जो एएमआर को दैनिक जीवन से जोड़ता है।

4. नीतिगत निहितार्थ

- **जन जागरूकता अभियानों में** संबंधित आख्यानों का उपयोग किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए, "अपने अच्छे बैक्टीरिया की रक्षा करें").
- **स्कूल पाठ्यक्रम** और सामुदायिक कार्यक्रमों को जिम्मेदार एंटीबायोटिक उपयोग सिखाना चाहिए।
- **डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को** एएमआर जोखिमों को सहानुभूतिपूर्वक संवाद करना चाहिए।
- **मीडिया स्टोरीटेलिंग** को रोगी के अनुभवों को उजागर करना चाहिए, न कि केवल वैश्विक आँकड़े।

निष्कर्ष

रोगाणुरोधी प्रतिरोध दुनिया की सबसे जरूरी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है - लेकिन इसके आसपास की बातचीत स्थिर हो गई है। ध्यान फिर से जगाने के लिए, हमें इस मुद्दे का मानवीकरण करना चाहिए, डर से सहानुभूति की ओर, संख्याओं से आख्यानों की ओर, और प्रतिरोध से लचीलेपन की ओर। एंटीबायोटिक दवाओं की रक्षा करना केवल दवाओं को बचाने के बारे में नहीं है - यह **हमारे अदृश्य सहयोगियों**, लाभकारी रोगाणुओं को संरक्षित करने के बारे में है जो मानव जीवन को बनाए रखते हैं। एएमआर कार्रवाई का भविष्य इस बात पर निर्भर करता **है कि हम कैसे बात करते हैं**

प्रश्न: रोगाणुरोधी प्रतिरोध अब केवल एक जैविक खतरा नहीं है, बल्कि एक संचार विफलता है। AMR का मुकाबला करने के भारत के प्रयासों के आलोक में इस कथन की जाँच करें। **(250 शब्द)**

दैनिक समाचार विश्लेषण

Page : 10: GS 2 : Indian Polity/ Prelims

मतदाता सूची की अखंडता एक कार्यशील लोकतंत्र की आधारशिला है। सटीक और अद्यतन सूची यह सुनिश्चित करती है कि केवल पात्र नागरिक ही अपने मताधिकार का प्रयोग करें और चुनावी धोखाधड़ी को रोकें। हाल ही में, **भारत के चुनाव आयोग (EC) ने बिहार में मतदाता सूचियों का** विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) **संपन्न किया** , जिसमें चुनाव से पहले स्वच्छ मतदाता सूचियों को बनाए रखने के लिए चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

What are the various electoral forms?

What is Form 6 used for in the context of electoral rolls? How can Overseas Electors register to vote? Which forms are used to raise objections or request corrections? What should citizens do to ensure their names are correctly included in the electoral rolls?

EXPLAINER

Rangarajan R.

The story so far:
The Election Commission (EC) has just concluded the special intensive revision (SIR) of electoral rolls in Bihar. It proposes to roll it out in other States in a phased manner.

What is the current significance?
Section 21 of the Representation of the People Act, 1950 (RP Act), deals with the preparation and revision of electoral rolls. A summary revision is carried out before each general election or by-election in any constituency. The RP Act also authorises the EC to carry out a special revision of the electoral roll at any time.

The EC, through its order dated June 24, had decided to conduct SIR for the entire country. Since the Bihar Assembly elections are due in November, the Commission issued guidelines for the SIR of the Bihar electoral roll, with July 1 as the qualifying date.

The SIR process in Bihar involved submission of enumeration forms by all registered voters, submission of any eligible documents to prove citizenship (for electors registered after 2003), publication of draft electoral rolls based on forms submitted, a period for filing claims and objections, verification and disposal of claims and objections by the Electoral Registration Officers (ERO), and publication of final roll.

The SIR process was challenged in the Supreme Court. In its interim orders, the court had directed the EC to accept Aadhaar as one of the eligible documents to be submitted along with the enumeration forms as proof of identity. The final roll for Bihar was released by the EC on September 30. The Commission proposes to complete the SIR process for the entire country in a phased manner based on the Assembly election schedules for various States.

Various forms with respect to electoral rolls as per RER

Form Number	Description
Form 6	Application to be submitted by new voters to be registered as an elector. As per section 19 of the RP Act, the qualifying dates for completion of 18 years of age, are 1st day of January, April, July and October of the year in which the electoral roll is prepared or revised.
Form 6A	Form for inclusion by an Overseas Elector. Non-Resident Indians who have shifted out of India, on account of education, employment or otherwise, can register as an elector in the constituency in which their address as per passport is located.
Form 7	Objection for proposed inclusion/deletion of name from existing roll. This form can be filed by a registered elector in a constituency in respect of any other registered elector or proposed inclusion in the roll or for deletion of applicant's own name.
Form 8	Form for shifting residence/correction of entries. This form can be filed by a registered elector for shifting of residence or correction of entries.
Form 5	Notice of publication of draft electoral roll by the ERO.
Form 9	List of applications for inclusion of names received in Form 6.
Form 10	List of applications for objection to inclusion of names received in Form 7.
Form 11	List of objections/applications for correction of entries received in Form 8.
Form 11A	List of applications for shifting of address within the constituency received in Form 8.
Form 11B	List of applications for shifting of address outside the constituency received in Form 8.

*Forms 9 to 11B are prepared and published by the ERO

Field work: A Booth-Level Officer checks documents during the special intensive revision of the electoral roll, Araria district, Bihar, on July 8. Shashi Shekhar Kashyap

What are the various forms?
In the present context, it is important for citizens to be aware of the various forms that deal with electoral rolls. These forms are provided in the Registration of Electors Rules, 1960 (RER). A brief summary of all the important forms as per RER is provided in the Table given above. It also contains detailed guidelines for filling out the application with respect to each of these forms.

What should citizens do?
There are political arguments both for and against the SIR exercise as carried out in Bihar. However, clean electoral rolls are paramount for the conduct of free and fair elections, which is essential for our functioning democracy. The EC would hopefully devise a more spread-out schedule in future SIRs that provides adequate time for hassle-free participation by voters. The list of eligible documents is also likely to include Aadhaar as proof of identity, in subsequent SIRs as per the Supreme Court directive.

Citizens should ensure that they verify the published draft rolls. They should fill out the enumeration forms as required. New voters and electors who have migrated to different constituencies should fill out the relevant forms

Meanwhile, citizens should ensure that they verify the published draft rolls. They should fill out the enumeration forms as required.

New voters and electors who have migrated to different constituencies should fill out the relevant forms. Political parties and civil society groups should assist citizens, especially the most marginalised sections, throughout the process. This would ensure a clean electoral roll without compromising on the right to vote of every eligible citizen.

Rangarajan R is a former IAS officer and author of 'Courseware on Polity Simplified'. He currently trains at Officers IAS academy. Views expressed are personal

THE GIST

- The Election Commission conducted a special intensive revision (SIR) of electoral rolls, starting with Bihar, requiring voters to submit enumeration forms and proof of identity.
- Citizens should verify draft rolls, submit the relevant forms if they are new voters or have migrated, and seek assistance from political parties and civil society to ensure clean electoral rolls without compromising the right to vote.

स्थैतिक संदर्भ

दैनिक समाचार विश्लेषण

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम), विशेष रूप से **धारा 21**, मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन को नियंत्रित करती है। मतदाता सूची को समय-समय पर निम्नलिखित के माध्यम से संशोधित किया जाता है:

1. **सारांश पुनरीक्षण** – किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में आम चुनाव या उपचुनाव से पहले आयोजित किया जाता है।
2. **विशेष संशोधन** - चुनाव आयोग के विवेक पर कभी भी आयोजित किया जा सकता है।

निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 (आरईआर) नागरिकों को मतदाता सूची में प्रविष्टियों को पंजीकृत करने, अपडेट करने या चुनौती देने के लिए प्रपत्रों का एक सेट प्रदान करता है।

आरईआर के तहत प्रमुख प्रपत्र:

रूप	लक्ष्य
फॉर्म 6	नया मतदाता पंजीकरण (मतदाता सूची में नाम शामिल करना)
फॉर्म 7	नाम शामिल करने या गलत प्रविष्टियों की रिपोर्ट करने पर आपत्ति
फॉर्म 8	प्रविष्टियों के सुधार के लिए आवेदन (जैसे नाम, पता, आयु)
फॉर्म 8A	प्रविष्टि को स्थानांतरित करने (स्थानांतरण) के लिए जब कोई मतदाता किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जाता है
फॉर्म 6A	प्रवासी मतदाताओं **के लिए पंजीकरण** (विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक)

विदेशी मतदाता कैसे पंजीकरण करते हैं:

- फॉर्म 6ए के **माध्यम से**, विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय नागरिक **ईसीआई पोर्टल के माध्यम से** या भारतीय दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

नागरिक जिम्मेदारियां:

- चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची का सत्यापन करें।
- नए पंजीकरण के लिए **फॉर्म 6** जमा करें।
- आपत्तियों, सुधारों या निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म **7, 8, 8A का** उपयोग करें।
- नागरिकता साबित करने वाले वैध दस्तावेज जमा करना सुनिश्चित करें (2003 के बाद, **आधार जैसे दस्तावेज** स्वीकार किए जाते हैं)।

वर्तमान संदर्भ

बिहार में एसआईआर में शामिल हैं:

1. सभी पंजीकृत मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र जमा करना।

2. नागरिकता दस्तावेजों का सत्यापन।
3. मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन।
4. नागरिकों द्वारा दावे और आपत्तियां दर्ज करना।
5. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) **द्वारा दावों और आपत्तियों का निपटान**।
6. चुनाव से पहले अंतिम सूची का प्रकाशन।

सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन के दौरान पहचान के प्रमाण के रूप में आधार के उपयोग की अनुमति दी। बिहार एसआईआर विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के अनुरूप अन्य राज्यों में चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक मिसाल कायम करता **है**।

महत्व :

- स्वच्छ मतदाता सूची चुनावों की विश्वसनीयता को बढ़ाती है।
- वंचित नागरिकों और प्रवासियों को मताधिकार से वंचित होने से रोकने के लिए भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- राजनीतिक दल और नागरिक समाज समूह इस प्रक्रिया के दौरान नागरिकों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों **के लिए सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है**, जो भारत के लोकतंत्र का आधार है। नागरिकों को सक्रिय रूप से अपनी प्रविष्टियों को सत्यापित करना चाहिए, आवश्यक फॉर्म जमा करने चाहिए और अपना विवरण अपडेट करना चाहिए। पहचान के प्रमाण के रूप में आधार के साथ चुनाव आयोग के चरणबद्ध एसआईआर दृष्टिकोण का उद्देश्य चुनावी अखंडता की रक्षा करते हुए मतदाता पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना है। नागरिकों, नागरिक समाज और राजनीतिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पात्र मतदाता मतदान के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करे।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत किया जाता है।

2. यह चुनाव आयोग द्वारा किसी भी समय आयोजित किया जा सकता है।

3. आधार का उपयोग 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं के लिए नागरिकता के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।

विकल्प:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

उत्तर: d)

UPSC Mains Practice Question

भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में SIR के महत्व पर चर्चा करें। सटीक मतदाता सूची बनाए रखने में नागरिकों और नागरिक समाज की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। **(150 शब्द)**

Page 14 : GS 2 : International Relations / Prelims

सितंबर की शुरुआत में जनरल जेड के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन **के बाद नेपाल एक अशांत राजनीतिक चरण से गुजर रहा है** , जिसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था। सोशल मीडिया प्रतिबंधों, भ्रष्टाचार की शिकायतों और कुशासन से प्रेरित विरोध प्रदर्शनों ने दक्षिण एशियाई लोकतंत्रों में युवा सक्रियता के बढ़ते प्रभाव को उजागर किया। **अगले चुनावों में 150 दिन से भी कम समय बचा है**, देश को लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

दैनिक समाचार विश्लेषण

A month since the Gen Z protests, Nepal faces a tough road to democratic reform

With less than 150 days to the elections, Nepal's interim administration is struggling to find its feet after a Gen Z-led uprising shook the establishment; analysts call it hastily stitched together and lacking firm political ground; meanwhile, traditional parties sidelined by the protests are now resurfacing

NEWS ANALYSIS

Sanjeev Satgainya
KATHMANDU

Thursday marked a month since Nepal, especially the capital Kathmandu, witnessed anarchy. On September 9, a day after the youth-led protests, then Prime Minister K.P. Sharma Oli resigned and fled to an army barracks following the deaths of 19 young people.

The Nepali capital saw events of an unprecedented degree – the Parliament, government complex, and the Supreme Court burned till late into the night.

Since September 12, an interim Cabinet led by former Chief Justice Sushila Karki has been in place, with the mandate of holding elections on March 5. The official death toll of the two-day protests stands at 75.

The month since the protests has been uneasy, punctuated by festival holidays and rain-induced disasters. A proposed protest plan by a youth group for October 9 stirred fresh anxiety, though it was ultimately withdrawn a day before after some groups dissociated themselves.

One youth group also demanded the resignation of the chief and members of the Commission for the Investigation of Abuse of Authority – Nepal's top constitutional anti-graft agency.

These youth groups, broadly dubbed under the umbrella of Gen Z, led last month's demonstrations, which were triggered by a social media ban and driven by anger at corruption and misrule. Now, they appear scattered and fragmented, which analysts say was inevitable given their structureless and leaderless nature.

Mourning their loss: Family members of protesters who died hold a candlelight vigil in front of the damaged parliament building in Kathmandu on Thursday. AFP

However, campaigners argue that lacking formal leadership is not a flaw.

Rakshya Bam, who organised and participated in the protests, said the youth took to the streets with specific demands – ending corruption and rolling back the social media ban. "But as the situation unfolded, we are where we are today," Ms. Bam said.

Government in a bind

As anarchy descended on Kathmandu on September 9 – with overwhelmed security agencies unable to maintain law and order – the Nepal Army stepped in not only to secure the capital but also to facilitate dialogue with President Ram Chandra Poudel.

It was at Army Headquarters that youth campaigners finalised Ms. Karki's name after she won a vote on the digital platform Discord, a virtual public square for Gen Z, where they planned their protests.

Analysts describe this interim administration as hastily stitched together, backed by Gen Z but lacking solid political ground. Within hours of her oath, PM Karki dissolved the House of Representatives.

"A lack of political nature is the biggest challenge of this government," said Keshav Dahal, a writer and political commentator. "The government and political parties appear to hold each other in deep contempt, which is likely to spoil the environment for elections."

Nepal's traditional parties, consigned to the back foot after the protests, are now resurfacing.

Deposed PM Oli addressed his party members on Thursday, dismissing the current government.

"Many say we have to wait till March 5 and should demand the restoration of the House if elections do not take place," he told them, hinting at moving the Supreme Court for reinstatement of the House. "The House dissolution is unconstitutional, illegal, and undemocratic."

His remarks come amid political parties' refusal to commit to the March 5 elections. Concerns mount over whether the elections will take place as scheduled – and if they do, whether they will carry legitimacy if major parties boycott.

Gen Z campaigners say it's incumbent on everyone to work towards protecting democracy.

"The interim government needs support from all sides – citizens, civil society, intellectuals, and political parties – to conduct timely elections," said Ms. Bam. "After all, our protests did not mean – and we do not wish – to prohibit parties. They are key constituents in a multi-party democratic set-up."

As the country eyes elections, accusations and counter-accusations are flying. Last week, social media buzzed with calls to arrest Mr. Oli and Ramesh Lekhak, who was Home Minister when 19 protesters were killed.

After an initial refusal, police agreed to accept complaints filed by those injured during the protests against Mr. Oli and Mr. Lekhak, with the caveat that the case would be forwarded to a judicial commission investigating the September 8-9 incidents. But the commission, led by a former judge, on Thursday sent the case back to police, saying investigation authority lies with the state apparatus.

Meanwhile, a student wing affiliated with Mr. Oli's Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) seeks to file a treason complaint against Balendra Shah, Kathmandu Mayor, and Sudan Gurung, a self-styled Gen Z leader.

Economic costs

For a country already struggling economically, last month's protests dealt a heavy blow. The World Bank revised Nepal's growth forecast to 2.1% for fiscal year 2025-26, down from the earlier 5.4%.

In its South Asia Development Update, the multilateral agency said the September 8-9 unrest deepened political and economic uncertainty in Nepal. It warned that international tourist arrivals are likely to see a sharp drop, and weakened investor confidence could slow private investment.

Yug Pathak, writer and analyst, says the government can prove its legitimacy only by holding elections on time; otherwise, the risk of plunging Nepal into deep uncertainty and instability persists.

"It's difficult to pinpoint who was involved or how peaceful protests went awry, but the events have left Nepal at a critical juncture."

Delayed dialogue

The Election Commission (EC) has called on any group intending to contest the March 5 elections to register as a political party by November 16. Earlier this week, Ms. Karki asked the EC to launch talks with political parties.

Analysts say the government, not the EC needs to lead dialogue with political parties.

Government sources say modalities are being worked out for dialogue. "Talks will begin soon to bring parties into confidence," said a government source, declining to elaborate or give a timeline.

But time is of the essence, and analysts say the government has yet to grasp the urgency. With less than 150 days to go for polls, youth campaigners agree that the government must rise to the occasion.

"Parties must reform, the system must function, and institutions must be strengthened to lay the ground for democracy to thrive," said Ms. Bam.

स्थैतिक संदर्भ

- नेपाल एक बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र **के तहत काम करता है** , जिसमें एक राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख और एक प्रधान मंत्री कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में होता है।
- **अंतरिम सरकारों को** संवैधानिक रूप से चुनाव कराने और राजनीतिक संकट के मामले में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया गया है।
- ऐतिहासिक रूप से, नेपाल ने राजनीतिक अस्थिरता देखी है, सरकार में लगातार बदलाव, संवैधानिक सुधार, और राजशाही से गणतंत्र (2008) में संक्रमण के साथ।

वर्तमान संदर्भ

जनरल जेड विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया:

- 9 सितंबर, 2025 **को** काठमांडू में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया; **19 प्रदर्शनकारियों की तुरंत मौत हो गई**, दो दिनों में **आधिकारिक संख्या बढ़कर** 75 हो गई।
- प्रदर्शनकारियों ने डिस्कॉर्ड **के माध्यम से डिजिटल रूप से संगठित** होकर सोशल मीडिया प्रतिबंधों और भ्रष्टाचार को निशाना बनाया। संसद, सरकारी कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट परिसर क्षतिग्रस्त हो गए।
- **ओली ने इस्तीफा दे दिया** और अंतरिम प्रधान मंत्री **सुशीला कार्की, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, को** सेना द्वारा 5 मार्च, 2026 **को होने वाले चुनावों की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया**।

अंतरिम प्रशासन के सामने चुनौतियाँ:

- विश्लेषकों ने सरकार को **"जल्दबाजी में एक साथ सिले" के रूप में वर्णित किया है**, जो जेन जेड द्वारा समर्थित है, लेकिन दृढ़ राजनीतिक वैधता का अभाव है।
- विरोध प्रदर्शनों के दौरान दरकिनार किए गए राजनीतिक दल फिर से उभर रहे हैं। ओली की पार्टी और अन्य पारंपरिक ताकतें सदन को भंग करने को चुनौती दे रही हैं और चुनावों के बहिष्कार की धमकी दे रही हैं।
- जेन जेड कार्यकर्ता **नेतृत्वहीन और खंडित** रहते हैं, जो सुधारों पर निरंतर दबाव को कम करता है लेकिन आंदोलन के पदानुक्रमित वर्चस्व से बचता है।

आर्थिक और संस्थागत प्रभाव:

- विरोध प्रदर्शनों ने **आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ा दिया है; विश्व बैंक ने** वित्त वर्ष 2025-26 के लिए **नेपाल के विकास अनुमान को** 5.4% से संशोधित कर 2.1% कर दिया है।
- निवेशकों के विश्वास और पर्यटन में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे विदेशी मुद्रा और विकास परियोजनाएं प्रभावित होंगी।
- कानूनी और जांच तंत्र तनाव का सामना करते हैं; अधिकारियों की ओवरलैपिंग के कारण पूर्व नेताओं के खिलाफ मामले अधर में लटके हुए हैं।

चुनाव और संवाद की तात्कालिकता:

- चुनाव आयोग ने 16 नवंबर **तक राजनीतिक पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है**।
- विश्लेषकों ने जोर देकर कहा कि अंतरिम सरकार को **पार्टियों को शामिल करना चाहिए, संस्थानों को मजबूत करना चाहिए और** वैधता स्थापित करने और लोकतांत्रिक कामकाज को बहाल करने के लिए समय पर चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए।

लोकतंत्र के लिए निहितार्थ

1. **युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन** दक्षिण एशिया में राजनीतिक प्रवचन को नया आकार दे रहे हैं, जवाबदेही, डिजिटल सक्रियता और भ्रष्टाचार विरोधी मांगों पर जोर दे रहे हैं।
2. **राजनीतिक वैधता के बिना अंतरिम शासन अस्थिरता, विलंबित सुधारों और कमजोर आर्थिक प्रदर्शन का जोखिम उठाता** है।
3. **लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास को फिर से स्थापित करने और आगे ध्रुवीकरण को रोकने के लिए** समय पर चुनाव महत्वपूर्ण हैं।
4. नेपाल का परिदृश्य नाजुक **लोकतंत्रों में** विरोध आंदोलनों, पारंपरिक राजनीति और संवैधानिक तंत्र के बीच परस्पर क्रिया को उजागर करता है।

निष्कर्ष

दैनिक समाचार विश्लेषण

नेपाल एक महत्वपूर्ण मोड़ **पर खड़ा है** जहां युवा सक्रियता, राजनीतिक पुनर्गठन और आर्थिक अनिश्चितता का अभिसरण इसके लोकतंत्र के प्रक्षेपवक्र को परिभाषित कर सकता है। जेन जेड द्वारा समर्थित अंतरिम प्रशासन को पारंपरिक दलों के साथ अंतराल को पाटना चाहिए, समय पर चुनाव कराना चाहिए और संस्थानों को मजबूत करना चाहिए। ऐसा करने में विफलता लंबे समय तक अस्थिरता, आर्थिक मंदी और लोकतांत्रिक शासन में जनता के विश्वास के क्षरण का जोखिम उठाती है। नेपाली मामला दक्षिण एशियाई लोकतंत्रों के लिए व्यापक सबक को रेखांकित **करता है: समावेशी संवाद, संस्थागत वैधता और नागरिक जुड़ाव लोकतांत्रिक समेकन के लिए अपरिहार्य हैं।**

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: नेपाल में जेन जेड के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन राजनीतिक प्रक्रियाओं को आकार देने में युवा सक्रियता के बढ़ते प्रभाव को उजागर करते हैं। भारतीय संदर्भ में, लोकतंत्र को मजबूत करने में युवा आंदोलनों की भूमिका और शासन के लिए उनके द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। **(150 शब्द)**

Page : 08 Editorial Analysis

India's mental health crisis, the cries and scars

Amal Chandra

is an author, policy analyst and columnist

Naimisha

is the founder and CEO of Youthocracy and is building Umeed, an Artificial Intelligence-powered mental health support platform

In Shahjahanpur, Uttar Pradesh, a young couple recently ended their lives after poisoning their four-month-old son. They left behind a note wanting their home and car to be sold to repay their debts. Months earlier, the media reported that several students in Kota, Rajasthan, which is called the nation's coaching hub, had died by suicide. Treated individually as anomalies, these tragedies highlight a crisis in India – a grim national mental health crisis spanning villages, cities, classrooms, boardrooms, farms and homes.

The data from across India

According to the National Crime Records Bureau's Accidental Deaths and Suicides in India (ADSI) 2023 report, there were 1,71,418 suicides in India – a rise of 0.3% from the previous year. Yet, the suicide rate per 1,00,000 population fell marginally by 0.8%, indicating that population growth had outpaced case increases. The Andaman and Nicobar Islands, Sikkim and Kerala reported the highest suicide rates, while Maharashtra, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Karnataka, and West Bengal accounted for more than 40% of all deaths. Cities continued to have higher suicide rates than in rural India, reflecting the pressures of urban life. Men made up 72.8% of all victims, revealing gendered economic and social stress. Family problems accounted for nearly a third (31.9%) of suicides, followed by illness (19%), substance abuse (7%), and relationship or marriage-related issues (about 10% combined).

Distress in the agrarian sector persists, with 10,786 farmer suicides, around 6.3% of the total reported in 2023, slightly lower than the previous year. Most cases were in Maharashtra and Karnataka. But there is a broader crisis – since 2014, over 1,00,000 farmers have taken their lives. Between 1995 and 2015, nearly 2,96,000 of the cases were the result of debt, crop failure, market shocks and institutional neglect. Equally invisible are homemakers and caregivers, predominantly women, who face high rates of depression, marital distress and domestic violence but do not feature in official statistics.

It was against this backdrop that one of us, on an ordinary morning, felt the weight of existence suddenly unbearable – not from illness or exhaustion, but from a numbing sense that every small act, such as brushing one's teeth to answering a message, had lost meaning. There was food in the fridge, work in progress, and no visible crisis, yet the heaviness was overwhelming. In that moment of quiet panic, reaching out to an Artificial Intelligence (AI) platform felt safer than speaking to someone.

> The government should prioritise mental health and counselling must become a public infrastructure

Why does technology seem more approachable than human company? It was a moment that captured a painful truth: countless Indians are confiding in algorithms because they have no one else to turn to. This is not a technological failure, but a human one.

Nearly 230 million Indians live with mental disorders, from depression and anxiety to bipolar and substance-use conditions. Yet, over four in five persons with severe illness receive no formal care due to stigma, the cost, and a severe shortage of professionals. Lifetime prevalence sits at 10.6%, with treatment gaps that range from 70% to 92%. Even as official suicide rates appear stable, the World Health Organization (WHO) estimates 16.3 deaths per 1,00,000 people, highlighting India's heavy mental health burden. Behind these numbers are lives such as a young university student who jumped off a bridge after leaving behind a note that she felt "unworthy" – a word that echoes quietly in hostels, offices and unread messages, and denoting silent despair.

Gaps in the system

India's mental health system needs attention. With just 0.75 psychiatrists for 1,00,000 people, well below the WHO minimum of 1.7, and far from the ideal three, besides a similar shortage of nurses, psychologists and social workers, care is scarce. In schools and colleges, "counselling" often means a part-time teacher for thousands of students; in coaching hubs and universities, support is tokenistic and underfunded. On paper, laws appear progressive: the Mental Healthcare Act (2017) decriminalised suicide and guaranteed mental health care, while the National Suicide Prevention Strategy (2022) aimed to reduce deaths by 10%. Yet, suicides have risen.

Manodarpan, the school-based psycho-social support scheme, remains largely inactive, and despite 47 postgraduate psychiatry departments and 25 centres of excellence being sanctioned, staffing, pay and training gaps persist. Even the ₹270-crore mental health budget has been largely unspent, leaving policies as empty promises.

Today, millions of Indians turn to AI tools such as ChatGPT – not out of trust but out of loneliness. The OpenAI CEO, Sam Altman, himself has acknowledged that many young users treat the platform as a therapist or life coach, despite its lack of confidentiality, crisis intervention or privacy guarantees. This reliance reflects not technological faith but institutional collapse. AI can assist. But without regulation, it risks becoming a dangerous substitute for real, protected human care.

India must treat mental health as an emergency, not as an afterthought. The government should prioritise mental health and establish a cross-ministerial task force that spans health, education, agriculture, and women and child welfare with independent funding and clear accountability. Within five years, the aim should be to have at least three to five mental health professionals for every 1,00,000 people, achieved through expanded training, scholarships and incentives for rural postings.

Counselling must become a public infrastructure, not a charity. Every school, college, district hospital and agrarian block should have a full-time trained counsellor or a direct link to one, funded by central budgets. It should not be left to non-governmental organisations or goodwill. Public campaigns must destigmatise help-seeking, share recovery stories, and normalise conversations about distress.

Special outreach is needed for high-risk groups such as farmers, homemakers, students, survivors of abuse, and caregivers. For farmers, counselling must go hand in hand with debt relief and livelihood support. Homemakers, often isolated, need community-based therapy networks. In coaching hubs such as Kota, mental health care must be continuous, institutional, and preventive.

On online support

At the same time, India must urgently regulate the digital mental health ecosystem. Emotional-support apps and AI tools should disclose privacy risks, carry mandatory disclaimers, embed crisis-response redirections, and provide real-time access to licensed professionals. Until robust ethical and legal frameworks exist, such tools cannot replace qualified human care.

What is at stake is not only life but also the moral and social fabric of the nation. Suicide remains the leading cause of death among India's youth aged 15-29 years and the country bears a disproportionate share of global female suicide deaths. Untreated mental illness could cost India over $1 trillion in lost GDP by 2030 – employers already lose over ₹1.1 lakh crore annually to absenteeism, attrition and burnout. Each suicide, each breakdown, is a silenced voice, a broken family, and a future cut short.

Every one of us has known the relief when someone or some system says these important words: "You matter". If India truly aspires to be modern, progressive and humane, it must prove this by saving the lives now slipping away in silence.

GS. Paper 2- सामाजिकन्याय

UPSC Mains Practice Question: भारतसमाजके सभी वर्गों को प्रभावित करने वाले बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, फिर भी देखभाल तक पहुंच अपर्याप्त है। भारत की मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली में परिमाण, कारणों, चुनौतियों और नीतिगत अंतराल पर चर्चा करें। इस संकट से निपटने के उपाय सुझाएं। (150 शब्द)

संदर्भ:

भारत एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट **का सामना कर रहा है**, जो छात्रों, किसानों, गृहणियों, शहरी पेशेवरों और हाशिए पर रहने वाली आबादी को समान रूप से प्रभावित कर रहा है। कोटा जैसे कोचिंग हब में आत्महत्याओं से लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों की आत्महत्याओं तक, और गृहिणियों और देखभाल करने वालों की मूक पीड़ा तक, मानसिक संकट समाज के सभी वर्गों में व्याप्त है। मानसिक स्वास्थ्य, नीति और सार्वजनिक प्रवचन में लंबे समय से उपेक्षित, महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के साथ एक राष्ट्रीय चिंता बन गया है।

संकट की भयावहता

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (ADSI 2023) **के अनुसार, भारत में** 1,71,418 आत्महत्याएँ **दर्ज की गईं**, जिनमें **72.8% पीड़ित पुरुष थे** । प्रमुख कारणों में पारिवारिक समस्याएं (31.9%), बीमारी (19%), मादक द्रव्यों का सेवन (7%), और रिश्ते या वैवाहिक समस्याएं (~10%) शामिल हैं। **2014 के बाद से किसानों की आत्महत्या** की संख्या 10,786 थी, जबकि व्यापक कृषि संकट ने **1 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली है**। शहरी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में उच्च आत्महत्या दर की रिपोर्ट करते हैं, जो शहर के जीवन के दबावकोदर्शाताहै।

लगभग **230 मिलियन भारतीय** मानसिक विकारों से पीड़ित हैं, फिर भी उपचार में अंतर **70% से 92% तक है**, जो एक विशाल अपूर्ण आवश्यकता को उजागर करता है। उच्च जोखिम वाले समूहों में उच्च दबाव वाले शैक्षणिक वातावरण में छात्र, आर्थिक तनाव का सामना करने वाले किसान, गृहिणियां, देखभाल करने वाले और दुर्व्यवहार से बचे हुए लोग शामिल हैं। लैंगिक आयाम स्पष्ट हैं, महिलाएं अवसाद, वैवाहिक संकट और घरेलू हिंसा से असमान रूप से प्रभावित होती हैं।

प्रणालीगत और नीतिगत अंतराल

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (2017) **जैसे प्रगतिशील कानून के बावजूद**, जिसने आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की गारंटी दी, कार्यान्वयन कमजोर बना हुआ है:

- **कार्यबल की कमी**: भारत में **प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 0.75 मनोचिकित्सक और 0.12 मनोवैज्ञानिक हैं**, जो डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित प्रति 1,00,000 मनोचिकित्सकों से बहुत कम है।
- **बुनियादी ढांचे की कमी**: स्कूलों और विश्वविद्यालयों में परामर्श सांकेतिक है; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अक्सर आवश्यक साइकोट्रोपिक दवाओं कीकमीहोतीहै।
- **बजटीय कम उपयोग**: आवंटित **₹270 करोड़ का मानसिक स्वास्थ्य बजट** काफी हद तक खर्च नहीं किया गया है।
- **खंडित शासन**: स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और श्रम मंत्रालयों के बीच खराब अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुसंगत नीतिगत कार्रवाई को सीमित करता है।
- **डिजिटल जोखिम**: भावनात्मक समर्थन के लिए एआई प्लेटफार्मों पर बढ़ती निर्भरता अकेलेपन और संस्थागत विफलता को दर्शाती है, फिर भी इन उपकरणों में संकट हस्तक्षेप, गोपनीयता और पेशेवर निरीक्षण का अभाव है।
- **कलंक:** 50% से अधिक भारतीय मानसिक बीमारी को व्यक्तिगत कमजोरी के रूप में देखते हैं, जो मदद मांगने को हतोत्साहित करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना में, भारत का उपचार अंतराल (70-92%) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके (40-55%) से कहीं अधिक है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बजटीय आवंटन काफी कम है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं काफी हद तक शहरी-केंद्रित रहती हैं, जिससे 70% ग्रामीण आबादी वंचित रह जाती है।

वर्तमान पहल और उनकी सीमाएँ

- **जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी)** 767 जिलों को कवर करता है, जो परामर्श, आउट पेशेंट सेवाएं और आत्महत्या की रोकथाम प्रदान करता है, फिर भी प्रभावशीलता राज्यों में भिन्न होती है।
- **मनोदर्पण** 11 करोड़छात्रों तक पहुंच गया है, जो स्कूल-आधारित मनो-सामाजिक सहायता प्रदान कर रहा है, लेकिन कवरेज अधूरा है और निरंतर के बजाय काफी हद तक निवारक है।
- **टेली मानस,** एक 24x7 हेल्पलाइन, ने 20 लाख से अधिक टेली-परामर्श सत्रों की सुविधा प्रदान की है, लेकिन स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ गहरी पैठ और एकीकरण की आवश्यकता है।

नीतिगत सिफारिशें

1. **बजटीय आवंटन बढ़ाएँ:** बुनियादी ढांचे, कार्यबल और दवा आपूर्ति में सुधार के लिए मानसिक **स्वास्थ्य खर्च को कुल स्वास्थ्य व्यय का** कम से कम 5% तक बढ़ाएँ।
2. **कार्यबल का विस्तार करें**: ग्रामीण पोस्टिंग के लिए प्रोत्साहन के साथ **प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 3-5 पेशेवरों को** सुनिश्चित करते हुए, **मध्य-स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य प्रदाताओं को** प्रशिक्षित और तैनात करें।
3. **सार्वजनिक परामर्श अवसंरचना: प्राथमिक** स्वास्थ्य देखभाल के साथ सेवाओं को एकीकृत करते हुए, **प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, जिला अस्पताल और कृषि ब्लॉक में पूर्णकालिक परामर्शदाता** स्थापित करें।
4. **डिजिटल विनियमन**: एआई और ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य उपकरणों को **गोपनीयता सुरक्षा उपायों, संकट पुनर्निर्देशन और लाइसेंस प्राप्त पेशेवरों तक पहुंच** को एम्बेड करना चाहिए।
5. **उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए लक्षित समर्थन**:
    - किसान: ऋण राहत और आजीविका कार्यक्रमों के साथ परामर्श को मिलाएं।
    - छात्र: स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग केंद्रों में निरंतर मानसिक स्वास्थ्य सहायता।
    - गृहिणियां और देखभाल करने वाले: समुदाय-आधारित चिकित्सा नेटवर्क।
6. **कलंक विरोधी अभियान**: कार्यस्थलों, स्कूलों और समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता, पुनर्प्राप्ति कहानियों और सामान्यीकृत बातचीत को बढ़ावा देना।
7. **निगरानी और जवाबदेही:** उपचार के पालन, ड्रॉपआउट और संसाधन आवंटन को ट्रैक करने के लिए **कैस्केड-आधारित मूल्यांकन प्रणाली** लागू करें।
8. **नीति अपडेट**: भारत के मानसिक स्वास्थ्य निदान ढांचे को **ICD-11** के साथ संरेखित करें, जिसमें जटिल PTSD, लंबे समय तक दुःख विकार और गेमिंग डिसऑर्डर जैसी उभरती स्थितियों को शामिल किया गया है।
9. **क्रॉस-मिनिस्ट्रियल समन्वय**: एक एकीकृत प्रतिक्रिया बनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, श्रम और कृषि नीतियों को एकीकृत करना।

निष्कर्ष

भारत का मानसिक स्वास्थ्य संकट एक **सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक आपातकाल** दोनों है, जिसके परिणाम जीवन, आजीविका और सामाजिक सामंजस्य पर पड़ते हैं। आत्महत्या 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण है, और अनुपचारित मानसिक बीमारी के कारण भारत को **2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में $ 1 ट्रिलियन से अधिक** का नुकसान हो सकता है। इसे संबोधित करने **के लिए तत्काल, अच्छी तरह से वित्त पोषित और समन्वित नीतिगत कार्रवाई** की आवश्यकता है, कानूनी गारंटी, कार्यबल विस्तार, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल निरीक्षण और कलंक को खत्म करने के अभियानों को एकीकृत करना। एक

आधुनिक, मानवीय भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **प्रत्येक नागरिक को समय पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच हो,** इस बात की पुष्टि करते हुए कि "आप**मायनेरखतेहैं**।